7 जून 2018

भारत का नॉर्डिक देशों से संबंध: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मूल्यांकन

डॉ. अंकिता दत्ता*

16-17 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वीडन यात्रा, ना केवल पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, बल्कि पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन द्वारा विस्तृत नॉर्डिक क्षेत्र के देशों से सम्बंध मजबूत करने का प्रयास भी था। सम्मेलन के माध्यम से भारत को डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ एक मंच पर मुलाकात करने तथा बातचीत करने का अवसर मिला।

दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन से मुलाकात की, वहां के व्यापारिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ गोलमेज बैठक की तथा प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री लॉफवेन के साथ बातचीत के एजेंडे में नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, व्यापार, स्मार्ट सिटीज और एनएसजी की सदस्यता जैसे मुद्दे महत्त्वपूर्ण थे। प्रधानमंत्री मोदी तथा प्रधानमंत्री लॉफवेन ने संयुक्त रुप से पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी की जिसकी विषय वस्तु थी, "भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: साझा मूल्य, पारस्परिक समृद्धि"। शिखर सम्मेलन में नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नवाचार तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया।

भारत-स्वीडन सम्बंध: एक समीक्षा

भारत और स्वीडन के बीच राजनयिक सम्बंध 1949 में आरम्भ हुए। दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय सम्पर्क 1957 से बढ़ने लगे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने स्वीडन की यात्रा की। 1972 में स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वीडन गईं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मार्च 1986 तथा जनवरी 1988 में दो बार स्वीडन की यात्रा की। स्वीडन के राजा गुस्ताफ ने भी दो बार, 1993 तथा 2005 में भारत का दौरा किया। हालांकि, बोफोर्स घोटाले और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद,

जिसपर नॉर्डिक देशों और विशेषकर स्वीडन ने कड़ी आपत्ति जताई थी, दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। लेकिन उसके बाद से भारत और स्वीडन के सम्बंधों में गहराई आई है, और आपसी समझ तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को लेकर सम्मान की भावना विकसित हुई है।

भारत तथा स्वीडन के सम्बंधों में उस समय प्रगाढ़ता आई, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में स्वीडन का दौरा किया। इस दौरे में दोनों देशों के बीच, सतत शहरी विकास, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग, राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा में छूट, ध्रुवीय तथा महासागर अनुसंधान, वृद्धावस्था एवं स्वास्थ्य, दवा उत्पादों जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े 6 समझौतों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तुरंत बाद, 2016 में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन मुंबई में आयोजित 'मेक इन इंडिया सप्ताह' में शामिल होने भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा स्टीफन लॉफवेन की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में रक्षा, मूलभूत ढांचा, शहरी विकास, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा अंतरिक्ष जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की पहचान की गई तथा इनमें द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक भारत-स्वीडन बिजनेस लीडर्स राउंडटेबल के निर्माण पर सहमति जताई, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष कारोबारी शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री का दौरा

2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दौरे तथा 2016 में स्वीडन के प्रधानमंत्री लॉफवेन के भारत दौरे से मजबूत हुए आपसी सम्बंधों को प्रधानमंत्री मोदी के हाल के दौरे से और गति मिली। स्वीडन, भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री लॉफवन के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा, "भारत एक वैश्विक शक्ति के रुप में उभर रहा है। कोई भी महत्त्वपूर्ण वैश्विक बातचीत बिना भारत की आवाज के पूरी नहीं हो सकती।" प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार, निवेश, स्टार्ट-अप्स, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया ताकि देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में, संयुक्त नवाचार भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर तथा संयुक्त कार्य योजना लागू करने पर सहमति मुख्य उपलब्धि रही। संयुक्त नवाचार भागीदारी समझौते तथा संयुक्त कार्य योजना का लक्ष्य था, विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत पहल करना। सहयोग के लिए जिन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई, वो हैं: -

नवाचार

प्रधानमंत्री के स्वीडन यात्रा में चर्चा का केन्द्र विन्दु था, नवाचार। ये बात और स्पष्ट हो गई, जब प्रधानमंत्री ने कहा "मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत का सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किस तरह स्वीडन, भारत के विकास के साथ उत्पन्न नये अवसरों की बदौलत, भारत के साथ एक ऐसी साझेदारी कर सकता है, जिसमें हर तरह से जीत तय हो। इसी के परिणामस्वरूप, हम एक नवाचार भागीदारी तथा एक संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए हैं।" उन्होंने कहा कि नवाचार, निवेश, स्टार्ट-अप्स, विनिर्माण आदि भारत तथा स्वीडन के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। दोनों देश एक स्थायी भविष्य के लिए संयुक्त नवाचार साझेदारी समझौते पर सहमत हुए, जिसके अन्तर्गत स्वीडन नवाचार सहयोग के लिए भारत को 50 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (59 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) तकनीकी सहयोग राशि देगा। सतत भविष्य के लिए भारत-स्वीडन नवाचार साझेदारी को लेकर जारी संयुक्त बयान के अनुसार "नवाचार साझेदारी भारत-स्वीडन के बीच विज्ञान तथा नवाचार सहयोग में उत्तरोत्तर बदलाव, आपसी समृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता, तथा वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, का नवाचार के द्वारा सामना करने के प्रयासों को दर्शाता है।" ये साझेदारी सह-वित्तपोषण, सह-विकास तथा सह-निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि पारस्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के पूरक सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग हो सके। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच सम्बंध अधिक मजबूत करेगी, जिनका आधार 2016 में मुंबई में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य तथा 2018 में स्टॉकहोम में संयुक्त कार्य योजना के द्वारा रखी गई थी। सहयोग के क्षेत्रों में ई-गतिशीलता युक्त स्मार्ट शहर तथा परिवहन, स्मार्ट उद्योग, डिजिटाइजेशन, स्टार्ट-अप्स तथा आईपीआर से जुड़े मुद्दे, नये पदार्थ एवं उन्नत विनिर्माण, अंतरिक्ष तथा वैमानिकी, चक्रीय और जैव-आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें जैव-पदार्थ शामिल हों; तथा जैव-औषधीय उपकरणों समेत स्वास्थ्य तथा जीवविज्ञान शामिल हैं।

समझौते में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आह्वान किया गया। इसमें नवाचार से जुड़े महत्तवपूर्ण मंत्रालयों तथा एजेंसियों के प्रमुख नवाचार हितधारकों के साथ 'स्वीडन-भारत नवाचार वार्ता' भी शामिल है, ताकि नवाचार नीति विकास के लिए समग्र रणनीतिक दिशा तय हो सके। वार्ता को एक विशेषज्ञ समूह का सहयोग और सुझाव मिलेगा। दूसरा, 'स्वीडन-भारत साझेदारी विकास गतिविधियां' (पीडीए), जिसके अन्तर्गत दोनों देश सहयोग के लिए चिन्हित क्षेत्रों में, भागीदारी विकास से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करेंगे, ताकि इनसे जुड़ी महत्त्वपूर्ण एजेंसियों, उद्योग जगत के धुरंधरों, संस्थाओं, शोध एवं विकास संस्थानों तथा अन्य अनुदान एजेंसियों के बीच नेटवर्किंग और सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। इनसे जुड़ी समान चुनौतियों की पहचान हो सके तथा संयुक्त परियोजनाएं विकसित हो सकें। पीडीए भारत-स्वीडन के वर्तमान विस्तृत नवाचार गतिविधियों की जानकारी देने तथा उनके प्रदर्शन का भी मंच होगा। तीसरा,

'स्वीडन-भारत संयुक्त औद्योगिक शोध एवं विकास परियोजनाएं', जिसमें दोनों देश द्विपक्षीय नवाचार परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दोनों देश चुनौतियों पर आधारित संयुक्त औद्योगिक शोध एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार परियोजनाएं आरम्भ करेंगे, ताकि दोनों पक्षों द्वारा पहचाने गये चुनौतियों तथा अवसरों पर काम हो सके। इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण एन+एन मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें सरकार तथा कारोबारी दोनों धन लगाएंगे। चौथा, 'स्वीडन-भारत स्टार्ट-अप सहयोग', जिसके अन्तर्गत दोनों देश स्टार्ट-अप नवप्रयोग में सहयोग के अवसरों की तलाश करेंगे, ताकि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास को मौद्रिक प्रस्तावों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति मिल सके। पांचवां, 'अनुसंधान एवं नवाचार आधारभूत ढांचा' तथा जिसमें दोनों देश अपने-अपने देशों में उपलब्ध शोध एवं नवप्रयोग से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं तक पारस्परिक पहुंच को सुगम बनाने के तंत्र की स्थापना की संभावनाएं तलाशेंगे।

संयुक्त कार्य योजना में नवप्रयोग पर भी बल दिया गया, जिसमें दोनों देशों ने जानकारी साझा करने तथा स्मार्ट सिटी, जिसमें पारवाहन-समेकित शहरी विकास शामिल हो, वायु प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे से ऊर्जा निर्माण, अपशिष्ट-जल उपचार आदि क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की तलाश का निर्णय लिया गया। साथ ही, विद्युतीय-परिवहन तथा नवीकरणीय ईंधन के साथ-साथ रेलवे से जुड़े क्षेत्रों, जैसे रेलवे नीति का विकास, सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं परिचालन रेलवे के रख-रखाव में जानकारी साझा करने तथा सहयोग की संभावनाओं की तलाश पर सहमति हुई। स्मार्ट, टिकाऊ तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एवं स्वीडन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के विकास जैसे, स्मार्ट मीटरिंग, मांग प्रतिक्रिया, अनुसंधान के द्वारा विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, क्षमता निर्माण, नीतिगत सहयोग तथा बिजनेस मॉडल समेत बाजार डिजाइन की आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर पारस्परिक सहयोग का फैसला किया। दोनों देशों में, भारत-स्वीडन नवाचार के द्वारा अभिनव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान, नवप्रयोग तथा कारोबारी सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई, इनमें भी विशेषकर उन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने का फैसला किया गया, जिनसे नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके।

रक्षा सहयोग

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग 2009 में हस्ताक्षर किये गए एक समझौते पर आधारित हैं, जिसमें भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य ग्रुप की स्थापना की गई थी। समझौता ज्ञापन रक्षा अधिकारियों के बीच आपसी हितों से जुड़े सहयोग के विभिन्न क्षेत्र सुनिश्चित करता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत तथा स्वीडन के बीच सम्बंधों में रक्षा तथा सुरक्षा समझौतों को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बताया। उन्होंने कहा कि, *"स्वीडन रक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्त्वपूर्ण सहयोगी रहा है तथा मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी स्वीडन रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत को मदद देता रहेगा। हमने सुरक्षा क्षेत्र तथा विशेषकर साइबर सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने का निर्णय किया है।"* दोनों देशों के नेता रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर तथा रक्षा में सहयोग के लिए वर्गीकृत जानकारी के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को अंतिम

रूप देने पर सहमत हुए। संयुक्त कार्य योजना में भारत तथा स्वीडन अपने-अपने सम्बंधित मंत्रालयों, एजेंसियों तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा "रक्षा सहयोग पर भारत-स्वीडिश वार्ता का विस्तार; 2018-19 में भारत तथा स्वीडन में भारत-स्वीडन रक्षा सम्मेलनों का आयोजन तथा आईएसबीएलआरटी के साथ मिलकर भारत में रक्षा उत्पादन में निवेश की संभावनाएं तलाशने," साथ ही "प्रमुख रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल उपकरणों के निर्माताओं (ओईएम्स) के साथ लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों (एसएमई) के लिए आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए औद्योगिक भागीदारों को प्रोत्साहित करें।"

व्यापार तथा निवेश

पारस्परिक आर्थिक हित भारत-स्वीडन सम्बंधों के मुख्य आधार रहे हैं। इसे और गति मिली जब 2015 में भारतीय राष्ट्रपति की स्वीडन यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने साल 2018 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। लेकिन भारत सरकार द्वारा शुरु किए गये आर्थिक सुधारों, जैसे विमुद्रीकरण, की वजह से 2016-17 में आपसी व्यापार 1.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया, जबकि 2015-16 में ये 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वैसे, 2017-18 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

क्रम संख्या		**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**
1.	**निर्यात**	686.15	733.45	740.47	683.64	708.93	771.50
2.	**आयात**	1,681.43	1,679.42	1,748.40	1,484.85	1,161.12	1,464.47
3.	**कुल व्यापार**	2,367.58	2,412.86	2,488.87	2,168.49	1,870.05	2,235.97

स्रोत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार (सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

भारत में स्वीडिश निवेश तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। वैसे भी स्वीडन का भारत में निवेश का लंबा इतिहास रहा है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में 170 से अधिक स्वीडिश संयुक्त उपक्रम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाईयां हैं, जिन्होंने 2008 से अब तक 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। पिछले एक दशक में, स्वीडन में भी भारतीय निवेश में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में, स्वीडन में आईटी समेत अन्य क्षेत्रों की 70 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं। ताजा अनुमान के अनुसार, स्वीडन में भारतीय निवेश करीब 700 से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है।

फरवरी 2016 में स्वीडन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बंधों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत-स्वीडन बिजनेस लीडर्स राउंडटेबल (ISBLRT) का गठन किया गया, जिसमें सीआईआई तथा भारत-स्वीडन बिजनेस काउन्सिल संयोजक की भूमिका निभाएंगे। वैसे भी, स्वीडन भारत के अहम अभियान 'मेक इन इंडिया' के सबसे उत्साही भागीदारों में एक रहा है। ये बात तब और स्पष्ट हो गई जब 2016 में मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त रुप से स्वीडन के पैवेलियन का उद्घाटन किया और अगले ही वर्ष स्वीडन ने मेक इन इंडिया: स्वीडन 2017 की मेजबानी की।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान व्यापार तथा निवेश भी वार्ता के केन्द्र विन्दु रहे। आपसी व्यापार को प्रोत्साहन देने तथा निवेश को दोनों दिशाओं में सुगम बनाने के लिए, एक संयुक्त कार्ययोजना पर सहमति हुई, जिसके अन्तर्गत भारत में स्वीडन का निवेश 'इन्वेस्ट इंडिया' के द्वारा तथा स्वीडन में भारत का निवेश 'बिजनेस स्वीडन' के द्वारा होगा। साथ ही भारत-स्वीडन व्यापारिक सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने के लिए ISBLRT को प्रोत्साहन दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्दे

भारत तथा स्वीडन ने आपसी सरोकार के महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे; जलवायु परिवर्तन, एजेंडा 2030, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, मानवीय मुद्दे एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बातचीत एवं सहयोग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के नुकसान से बचने के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करना अत्यावश्यक बताया तथा पेरिस समझौते पर अपने समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री लॉफवेन को भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (2021-22) में अस्थायी सदस्य के तौर पर तथा विस्तारित और संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं प्रधानमंत्री लॉफवेन ने अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया समूह, वेसेनार समझौता, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था तथा बैलेस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध द हेग कोड ऑफ कंडक्ट शामिल हैं, में भारत के हाल में प्रवेश का स्वागत किया तथा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने, आतंकी संगठनों के नेटवर्क तथा उनके वित्त

पोषण की समाप्ति तथा हिंसक अतिवाद के विरुद्ध अधिक एकता एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। इस संदर्भ में, दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक समझौते (CCIT) का मसौदा जल्द से जल्द तैयार करने की मांग की। भारत तथा स्वीडन की सह-मेजबानी में आयोजित भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद के विरुद्ध जंग का मुद्दा उठा। इस सम्मेलन में नॉर्डिक देशों ने आतंकवाद तथा सभी प्रकार के उग्रवाद की निन्दा की एवं वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में भारत के साथ हर प्रकार से सहयोग का वादा किया।

अन्य

सहयोग के उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा, संयुक्त कार्य योजना में निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर बल दिया गया : पहला, **महिलाओं का कौशल विकास तथा सशक्तिकरण :** महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहन देना**,** जिसके लिए विविध परियोजनाओं जैसे "क्राफ्टसमला" के द्वारा कौशलयुक्त रोजगार तथा उद्यम के अवसरों की तलाश करना। "क्राफ्टसमला" भारत तथा स्वीडन के कलाकारों द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में आरम्भ की गई एक परियोजना है, जिसमें महिलाओं को फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर, गोदाम प्रबंधन, फैक्ट्री में एसेम्बली ऑपरेटर जैसे कई क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, **अंतरिक्ष तथा विज्ञान :** अंतरिक्ष एजेंसियों एवं इससे जुड़ी अन्य संस्थाओं को समझौता-ज्ञापन के द्वारा आपसी सहयोग के लिए सहमत करना तथा विशेषकर पृथ्वी के अवलोकन/प्रेक्षण, ग्रहों की खोज तथा सैटेलाइट-ग्राउंड स्टेशन क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना। इसके लिए अन्य बातों के अलावा एक इंडो-स्वीडिश अंतरिक्ष सेमिनार का आयोजन किया जाएगा तथा एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वीडन के अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। साथ ही, स्वीडन तथा भारत के प्रतिनिधियों और यूरोपीय स्पालैशन सोर्स(ESS-European Spallation Source) के बीच सहयोग की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। तीसरा, **स्वास्थ्य सेवा :** स्वास्थ्य सेवा तथा जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन के द्वारा सहकार्यता को प्रोत्साहन देना, जिनमें स्वास्थ्य से जुड़े शोध, औषधि सतर्कता तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।

प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद

स्वीडन में प्रवासी भारतीयों की संख्या अच्छी-खासी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, स्वीडन में भारतीय मूल के करीब 25,720 लोग रहते हैं। इनमें अधिकतर आईटी कंपनियों में कुशल पेशेवर, प्रोफेसर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोध विशेषज्ञ हैं। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चार वर्षों के अथक प्रयासों के बाद आज दुनिया भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के रुप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की कई ऐसी उपलब्धियां गिनाईं, जिनसे गरीबी मिटाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा व्यवसाय की सुगमता बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में विकसित भारत बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किए हैं, ताकि 2022 में जब भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होंगे, तो एक नया भारत सामने होगा। देश के विकास में

प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत में निवेश का आमंत्रण दिया और कहा, “आप लोग स्वयं को भारत से सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव तक सीमित मत रखें। जो लोग नवप्रयोग, व्यापार तथा निवेश की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उभरते भारत में काफी संभावनाएं हैं।”

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

भारत तथा स्वीडन ने 17 अप्रैल 2018 को पहले ‘भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन : साझा मूल्य, पारस्परिक समृद्धि’ की सह-मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन, डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लोके रास्मुसेन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कट्रीना जैकोब्सडॉतिर तथा नॉर्वे की प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत तथा नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया तथा वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नवाचार एवं जलवायु परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने स्वीकार किया कि परस्पर संबद्ध दुनिया में नवोन्मेष तथा डिजिटल रुपान्तरण के द्वारा विकास को गति दी जा सकती है। शिखर सम्मेलन में, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा क्लीन इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं के द्वारा समृद्धि तथा सतत विकास के लिए, नवाचार एवं डिजिटल उपक्रमों को लेकर भारत की कटिबद्धता पर बल दिया गया। साथ ही नॉर्डिक देशों में उपलब्ध सामुद्रिक संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य तथा जीव विज्ञान और कृषि से जुड़ी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक सतत शहर परियोजना का स्वागत किया गया, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना में सहायता करना है।

प्रधानमंत्रियों ने विशेषरूप से उल्लेख किया कि भारत तथा नॉर्डिक देशों की अनोखी क्षमताओं के कारण व्यापार तथा निवेश विविधिकरण और पारस्परिक लाभप्रद समझौतों की अपार संभावनाएं हैं। बातचीत के दौरान, नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था के महत्त्व को स्वीकारते हुए आपसी समृद्धि तथा विकास के लिए खुले एवं समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। उन्होंने एक बार फिर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा तथा पेरिस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने अधिक स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा एवं इंधन, अधिक कार्यकुशल ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादन के अधिक स्वच्छ तरीकों के विकास के लिए लगातार प्रयास करने पर सहमति जताई।

संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार का मुद्दा भी शामिल किया गया, जिसमें सभी देशों ने इस संगठन में सुधार की आवश्यकता तथा स्थायी एवं अस्थायी दोनों तरह के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया, ताकि सुरक्षा परिषद् इक्कीसवीं सदी के यथार्थ के प्रति अधिक प्रतिनिधिक, जिम्मेदार, प्रभावशाली तथा अनुक्रियाशील हो। वैसे तो इन देशों ने व्यक्तिगत तौर पर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया ही था, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में एक समूह के तौर पर भारतीय दावेदारी के लिए दबाव बढ़ाया गया तथा

नॉर्डिक देशों ने इस बात पर स्पष्ट सहमति जताई कि भारत विस्तारित सुरक्षा परिषद् में, जिसमें स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई हो, स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। साथ ही नॉर्डिक देशों ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता के लिए भारत के आवेदन का स्वागत किया तथा "जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम पाने के लक्ष्य के साथ" रचनात्मकरुप से काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने स्वीकार किया कि आतंकवाद तथा हिंसक अतिवाद, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने मानवाधिकार, प्रजातंत्र तथा कानून के राज को लेकर अपने साझा मूल्यों पर आधारित वैश्विक सुरक्षा, जिसमें साइबर सुरक्षा शामिल है, पर चर्चा की तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से अलग, भारतीय सम्बंधों तथा व्यापार को उस समय काफी आवश्यक प्रोत्साहन मिला, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी नॉर्डिक देशों के शासनाध्यक्षों से अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की। इन बैठकों में आपसी सहयोग बढ़ाने तथा सम्बंधों को मजबूत करने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लोके रास्मुसेन से मिले तथा भारत डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने तथा नए सहयोगों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने जिन क्षेत्रों में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए उनमें ***पहला*** था सतत तथा स्मार्ट शहरी विकास को लेकर भारत के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा डेनमार्क के उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच। ***दूसरा***, पशुपालन तथा दुग्ध-उत्पादन के क्षेत्रों में भारत के पशुपालन विभाग, दुग्ध एवं मत्स्य-उत्पादन विभाग, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग तथा डेनमार्क के पशु-चिकित्सा एवं खाद्य प्रशासन, और खाद्य एवं पर्यावरण मंत्रालय के बीच। ***तीसरा***, खाद्य सुरक्षा के मामले में सहयोग के लिए भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण एवं डेनमार्क के पशु-चिकित्सा एवं खाद्य प्रशासन के बीच। ***चौथा***, कृषि क्षेत्र में शोध तथा शिक्षा को लेकर आपसी सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के बीच।

फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार तथा निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, अपशिष्ट प्रबंधन, स्टार्ट-अप्स के अवसर एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। भारत में फिनलैंड की करीब 100 कंपनियां कारोबार कर रही हैं, जिन्होंने कपड़ा, सड़क परिवहन, सूचना सुरक्षा, नाभिकीय तथा विकिरण सुरक्षा, व्यापार जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। वहीं आइसलैंड की प्रधानमंत्री कट्रीना जैकोब्सडॉतिर के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे आग्रह किया कि नीली अर्थव्यवस्था तथा भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए आइसलैंड की कंपनियां भारत को निवेश गंतव्य के तौर पर चुनें। साथ ही, हिन्दी भाषा के लिए ICCR चेयर के गठन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) तथा आइसलैंड विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग के साथ अपनी बैठक में व्यापार तथा निवेश, जहाजरानी एवं बंदरगाह विकास, नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, आईटी और हरित

परिवहन उपाय जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की आर्थिक संपूरकता का हवाला देते हुए नॉर्वे के पेंशन फंड को भारत के नये क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। नॉर्वे के पास सबसे बड़ा पेंशन फंड है, यानी तकरीबन 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसका प्रबंधन गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (GPFG) के हाथों में है। इसने 2017 के अंत तक में भारत में 11.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, जो 2016 के निवेश से 2.5 बिलियन डॉलर अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी निवेश के लिए भारत के खुलेपन की नीति को रेखांकित किया तथा नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण दिया।

उपसंहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ये दौरा, भारत की उभरती विदेश नीति को दर्शाता है तथा स्पष्ट करता है कि इसमें नॉर्डिक देशों की क्या भूमिका हो सकती है। स्वीडन की यात्रा तथा विस्तृत नॉर्डिक क्षेत्रों तक पहुंच के प्रयासों से इन देशों के साथ सम्बंधों को बेहतर बनाने की क्षमता का अंदाजा मिलता है। नॉर्डिक देशों ने महसूस किया कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत के साथ मजबूत भागीदारी, न सिर्फ वांछनीय बल्कि आवश्यक भी है ।

स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बंधों के महत्त्व को रेखांकित करते हूए शीर्ष स्वीडिश फर्मों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। संयुक्त कार्य योजना तथा संयुक्त नवाचार भागीदारी के साथ, दोनों देश एक स्थाई भविष्य और आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहू-हितधारक नवाचार भागीदारी आरम्भ कर सकते हैं, जिसके अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, महिलाओं का कौशल विकास तथा सशक्तिकरण, अंतरिक्ष एवं विज्ञान, तथा स्वास्थ्य एवं जीवविज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विस्तृत पहल की जा सकेगी।

रक्षा में भारत तथा स्वीडन ने साइबर सुरक्षा के मामले में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम चल रहा है, जिसमें गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा उनके पारस्परिक संरक्षण के साथ निजी क्षेत्र के हितधारकों को रक्षा तथा वैमानिकी के मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ मिलकर, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। तेजी से विकसित हो रहे इस रक्षा सम्बंध ने स्वीडन को भारतीय वायुसेना के सामने अपने साब एबी ग्रिपेन लड़ाकू जेट विमानों के प्रदर्शन का अवसर दिया है। वो भी ठीक उस समय, जब भारत ने 110 स्थानीय रूप से निर्मित विमानों की खरीद प्रक्रिया में बोलियों के लिए जुलाई 2018 तक का अंतिम समय दिया है। इससे पहले, सितंबर 2017 में मेक इन इंडिया कैंपेन को प्रोत्साहन देते हूए साब ग्रुप ने भारत में सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए अडानी ग्रुप के साथ टाई-अप करने की घोषणा की थी। इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों समूह, अगर भारतीय वायुसेना द्वारा चुने गये तो संयुक्त रूप से भारत में ग्रिपेन लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, नॉर्डिक देशों द्वारा भारत के उभरते वैश्विक कद को स्वीकार करने का द्योतक है। शिखर सम्मेलन का संयुक्त बयान न केवल उन क्षेत्रों को, जिनमें नॉर्डिक देश तथा भारत सहयोग कर सकते हैं, बल्कि दोनों के साझा मूल्यों को भी रेखांकित करता है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, खुले तथा समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणालियों, तथा विशेषकर "समृद्धि तथा विकास के लिए नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों के साथ खुले तथा समावेशी व्यापार" पर बल देते हुए, इन्हें अपने समर्थन का स्पष्ट संकेत देता है। हालांकि, नॉर्डिक देशों ने एनएसजी के लिए भारत की सदस्यता को व्यक्तिगत रूप से पहले भी समर्थन दिया है, लेकिन शिखर सम्मेलन के मंच से उन्होंने सामूहिक तौर पर भारत की सदस्यता का समर्थन किया तथा "जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम पर पहुंचने के उद्देश्य से" भारत के एनएसजी आवेदन को समर्थन देने पर सहमत हुए। भारत के लिए इनका समर्थन इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इन देशों का रुख आलोचनात्मक रहा है।

वैसे, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद, भारत की एक जिम्मेदार परमाणु-संपन्न देश के रूप में साख बन चुकी है। एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए नॉर्डिक देशों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक समर्थन, विशिष्ट भारत केंद्रित मानदंड पर आधारित है, जिसमें भारत ने अपनी गैर-प्रसार तथा निरस्त्रीकरण नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। भारत का दावा तबसे और भी मजबूत हो गया है, जबसे इसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा-मानकों के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की तथा अपने असैन्य नाभिकीय आधारभूत ढांचे को आईएईए के निरीक्षण के लिए खोल दिया। इसके अलावा, भारत वेसेनार समझौता, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) तथा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे अन्य अहम समूहों का सदस्य बन चुका है। अब नॉर्डिक देशों का ये समर्थन, भविष्य में शामिल होनेवाले देशों के लिए हाल के उभरते मानदंडों से जुड़ा है या नहीं, ये देखना बाकी है। क्योंकि नॉर्डिक देशों ने अब तक एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे किसी और देश को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है।

शिखर सम्मेलन के दौरान ये स्पष्ट स्वीकृति बनी कि एक परस्पर संबद्ध दुनिया में नवाचार तथा डिजिटल रुपांतरण का विकास, भारत तथा नॉर्डिक देश, दोनों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इन देशों ने अपनी अभिनव प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाते हुए सतत विकास तथा प्रगति प्राप्त की है तथा आज इस स्थिति में हैं कि भारत के मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, नॉर्डिक देश जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए नीतियां लागू करने में सबसे आगे रहे हैं। इन देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त की है, तथा इसलिए भारत के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत, को अंजाम तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संतोषजनक आर्थिक सम्बंध हैं। भारत-नॉर्डिक वार्षिक व्यापार लगभग 5.3 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जबकि नॉर्डिक का संचयी निवेश (FDI) 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन यात्रा तथा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने एवं समावेशी विकास को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। इसके अलावा, नॉर्डिक देश, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, पर्यावरण समाधान, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, कृषिगत आधारभूत ढांचा, कौशल विकास तथा नवाचार, जो भारत के विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं, में अग्रणी रहे हैं। ये समानता एवं द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में वृद्धि की क्षमता रखते हैं तथा दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे को दिए जा रहे वृहत्तर महत्त्व को इंगित करते हैं।

***

*डॉ. अंकिता दत्ता, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली

डिस्क्लेमर: आलेख में दिये गए विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।